



भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI)  
का दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र का मुखपत्र

# मेहनतकश की आवाज़

बुलेटिन • संख्या-2 • वर्ष 1  
14 अप्रैल 2019 • तीन रुपये • आठ पृष्ठ

## मेहनतकश जनता अपना स्वतन्त्र विकल्प खड़ा करके ही फासीवादी मोदी सरकार को हरा सकती है! मज़दूर पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाओ!

मज़दूर साथियो! मेहनतकश भाइयो और बहनो! कल पहले दौर का मतदान है। पूरे देश में मोदी सरकार के पाँच वर्षों में मज़दूरों-मेहनतकशों के जीवन में आयी तबाही के कारण मोदी सरकार के खिलाफ़ ज़बर्दस्त असन्तोष है। भाजपा और संघ परिवार इस असन्तोष से डरकर ही साम्प्रदायिक प्रचार और अन्धराष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन आप किसी भी कीमत पर साम्प्रदायिकता और अन्धराष्ट्रवाद के झाँसे में न फँसें। भाजपा और संघ परिवार के 'राष्ट्र' में आपका कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रवाद की सोच वास्तव में अम्बानी-अडानी जैसे पूँजीपतियों की सेवा करती है। यही कारण है कि जब भी मज़दूर और मेहनतकश अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो भाजपा और संघ परिवार उनके आन्दोलन को

“राष्ट्र-विरोधी” करार दे देते हैं। “राष्ट्र” क्या है? यह पूँजीपति वर्ग की कल्पना है जिसका इस्तेमाल वह हमें झाँसे में डालने, भटकाने और कुचलने के लिए करता है। हमारे लिए “राष्ट्र” शब्द का कोई अर्थ नहीं है, अगर उसका मतलब देश के 80 फीसदी मज़दूर, ग़रीब किसान और आम मेहनतकश नहीं हैं।

हम अपने देश से प्यार करते हैं। लेकिन देश कागज़ पर बना कोई नक्शा नहीं होता। देश उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। इन लोगों में से 80 प्रतिशत लोग मज़दूर, ग़रीब किसान और आम मेहनतकश लोग हैं। यही लोग इस देश के लिए सुई से लेकर जहाज़ तक हर चीज़ बनाते हैं। क्या इस देश का भाजपा और साथ ही अन्य पूँजीवादी चुनावबाज़ पार्टियों के घोषणापत्रों में कोई

स्थान है? नहीं! अगर होता तो ये सभी पार्टियाँ क्या ठेका प्रथा को समाप्त करने का वायदा नहीं करतीं? अगर होता तो क्या अमीरज़ादों पर टैक्स बढ़ाकर क्या इन पार्टियों की सरकारें आम मेहनतकश जनता के लिए रोज़गार गारण्टी, सबके लिए समान और निशुल्क शिक्षा, सबके लिए समान और निशुल्क दवा-इलाज, सबके लिए आवास की गारण्टी की व्यवस्था नहीं करतीं?

भाजपा से ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है कि वह हम मज़दूरों और मेहनतकशों की बात करेगी। जिस पार्टी को बड़े मालिकों और ठेकेदारों से 1035 करोड़ रुपये का चन्दा मिला हो, वह भला हमारी बात क्यों करने लगी? यही तो वजह है मोदी समेत भाजपा के सारे नेताओं (पेज 3 पर जारी)

## जो ठेका प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात न करे, हर उस पार्टी का पूर्ण बहिष्कार करो!

मज़दूर भाइयो और बहनो! आज हमारे जीवन की बुरे हालात के सबसे प्रमुख कारणों में से है ठेका प्रथा। यह एक नयी गुलामी की व्यवस्था है। देश में कुल मज़दूर आबादी का 93 प्रतिशत ठेका, दिहाड़ी और कैजुअल मज़दूरों के रूप में काम करती है। यानी ठेका, दिहाड़ी और कैजुअल मज़दूरों की संख्या 40-50 करोड़ से कम नहीं है। इन 40-50 करोड़ मज़दूर भाइयों और बहनों के जीवन की हालत क्या है? दो जून की रोटी जुगाड़ करने में उनकी कमर टूट जाती है। बच्चों को

अच्छी शिक्षा और चिकित्सा देना तो दूर की बात है। मुर्गी के दड़बों जैसी झुग्गी बस्तियों में हमारे बच्चों का बचपन बीमारी, कुपोषण और भुखमरी में बीतता है। इस ठेका प्रथा ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है।

भारत सरकार ने 1971 में ठेका मज़दूरी उन्मूलन व विनियमन कानून में वायदा तो यह किया था कि सभी नियमित किस्म के कामों पर से ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन 1971 के बाद से ठेका मज़दूरों की संख्या में दोगुनी-तिगुनी

की बढ़ोत्तरी हुई है। कांग्रेस या भाजपा की सरकार हो, या फिर बसपा-सपा या वाम मोर्चा की या फिर आम आदमी पार्टी की, सभी ने इस सवाल पर हम मज़दूरों को धोखा दिया है। अब तो कोई पार्टी ठेका प्रथा के उन्मूलन की बात भी नहीं करती है। आम आदमी पार्टी आखिरी पार्टी थी जिसने यह वायदा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वह यह वायदा भूल गयी क्योंकि स्वयं आम आदमी पार्टी में तमाम विधायक व नेता (पेज 4 पर जारी)

**मज़दूर पार्टी को वोट दो! मेहनतकश ने ठाना है!**  
**ठेकेदारी को चोट दो! पूँजीवाद को चोट दो! RWPI को जिताना है!**

# यह चुनाव आयोग है या भाजपा का चुनाव विभाग?

भारत के इतिहास में कभी भी चुनाव आयोग की ऐसी गयी-बीती हालत नहीं रही है। यह स्वाभाविक भी है। फ़ासीवाद की ख़ासियतों में से एक यह भी है कि यह पूँजीवादी जनवाद की तमाम “सम्मानित संस्थाओं” को अन्दर से खोखला बना देता है। पहले भी भारत में इन संस्थाओं की हालत ख़राब ही थी। लेकिन इज़्ज़त बचाने के लिए ये संस्थाएँ कुछ कदम उठाया करती थीं। लेकिन अब आप चाहे चुनाव आयोग पर निगाह डालें या फिर न्यायपालिका पर, ये मानो आज की फ़ासीवादी शासक पार्टी भाजपा और नरेन्द्र मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं।

भाजपा के नेता खुले तौर पर चुनावी रैलियों में भारतीय सेना को ‘मोदी की सेना’ बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ‘चेतावनी’ भर देकर रह जा रहा है। प्रधानमन्त्री एक सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल के परीक्षण के एलान के बूते चुनाव प्रचार कर रहा है, लेकिन उसमें चुनाव आयोग को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिख रहा है। बालाकोट हमले के बारे में झूठी बातें बोलकर उसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल खुले तौर पर हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अन्धा बना हुआ है! ‘नमो टीवी’ नामक एक चैनल मोदी के महिमामण्डन के लिए अचानक रहस्यमय तरीके से प्रकट होता है, लेकिन

चुनाव आयोग उस पर कोई कदम नहीं उठाता, वह भी तब जब कि इस चैनल के लिए कोई पंजीकरण या आज्ञा नहीं ली गयी थी! सारे कानूनों और नियमों को ताक पर रखकर हार की डर में परेशान भाजपा और संघ परिवार चुनाव की आचार संहिता की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रही है, लेकिन चुनाव आयोग शान्त है। ऐसे में, इस संस्था की तथाकथित निष्पक्षता की सच्चाई जनता के सामने आ गयी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट की व्यवस्था करके चुनावों में पारदर्शिता को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इस पर जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय से पूछता है कि क्या उसे ईवीएम पर भरोसा नहीं है! यह कैसा जवाब है? **चुनाव आयोग सभी ईवीएम मशीनों के साथ चुनावों में वीवीपैट की व्यवस्था करने से क्यों घबरा रहा है? क्या इसके पीछे कोई साज़िश तो नहीं? इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।** जब हालिया विधानसभा चुनावों में ही ईवीएम मशीनें सड़क पर पड़ी मिल रही थीं, भाजपा नेताओं के घर से बरामद हो रही थीं, जहां ईवीएम मशीनें रखी गयीं थीं, वहां अचानक लाइट चली जा रही थी और सीसीटीवी कैमरा बन्द हो जा रहे थे, तो क्या यह

शक़ लाज़िमी नहीं है कि भाजपा सरकार ईवीएम घोटाला करने पर आमादा है?

लेकिन इन सभी चिन्ताओं के विषय में चुनाव आयोग को कुछ नहीं कहना है! ऐसे में, यह शक़ लाज़िमी है कि चुनाव आयोग भाजपा के चुनाव विभाग के तौर पर काम कर रहा है। **ज़ाहिर है, फ़ासीवाद ने पूँजीवादी चुनावों की पूरी प्रक्रिया को ही बिगाड़कर रख दिया है।**

आम मेहनतकश जनता को इन बारे में चौकस रहना चाहिए। चुनाव का पूँजीवादी जनवादी हक़ हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने मज़दूर वर्गीय राजनीतिक संघर्ष को पूँजीवादी जनवाद के रहते हुए तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं और चुनने और चुने जाने का अधिकार (हालाँकि मज़दूर वर्ग के लिए ‘चुने जाने के अधिकार’ में इतनी बाधाएँ खड़ी कर दी जाती हैं, कि वह आम तौर पर चुनाव में इस अधिकार का उपयोग ही नहीं कर पाता है) पूँजीवादी जनवाद का सबसे बुनियादी अधिकार है। **इस अधिकार को पूर्ण बनाने के लिए भी संघर्ष किया जाना चाहिए और इसे बचाने के लिए भी।** इसलिए अगर चोर दरवाज़े से इस अधिकार को फ़ासीवादी मोदी सरकार नष्ट करने का प्रयास करती है, तो हमें ज़रूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर कर इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

## मोदी सरकार के दौर में न्यायपालिका की हालत

हाल में ही एक मसला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आया है, जिससे पता चलता है कि मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था में सबसे पवित्र निकाय माने जाने वाले न्यायपालिका की हालत क्या हो चुकी है और उसकी असलियत क्या है।

सर्वोच्च न्यायालय में 2009 से ही एक याचिका दायर थी जिसके तहत पूछा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को सूचना के अधिकार के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। मौजूद नियुक्ति की व्यवस्था में कोई पारदर्शिता नहीं है और जनता का इस प्रक्रिया पर कोई नियन्त्रण नहीं है। ऐसे में, विभिन्न शासक पार्टियाँ इन नियुक्तियों का उपयोग अपने हितों के अनुसार करती रही हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन फ़ासीवादी मोदी सरकार के दौर में जिस नंगेपन के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, उसने पूँजीवादी न्यायपालिका के चेहरे पर निष्पक्षता और न्यायपूर्णता का जो पर्दा था वह लगभग उतार ही दिया है। हालत यह हो गयी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही प्रेस कान्फ्रेंस करके मोदी सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका के साथ हो रही छेड़छाड़ पर आपत्ति रखनी पड़ी! **ये समझदार न्यायाधीश थे, जिन्हें यह पता था कि यदि न्यायपालिका पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ गया तो यह पूँजीवादी व्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक होगा।**

लेकिन अभी जो मसला सामने आया है,

उसने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता की सच्चाई और साथ ही मोदी सरकार के न्यायपालिका को लेकर नापाक इरादों को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया है।

सरकार के प्रतिनिधि एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने इस याचिका का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की बेंच के सामने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इससे “संवेदनशील बातें” खुल जाएँगी! **ज़रा सोचिये कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार और न्यायपालिका के बीच कौन-सी संवेदनशील बातें होती हैं!? ज़ाहिर है, शासक वर्गों के हितों के लिए न्यायपालिका के फैसले और उसका हस्तक्षेप बाधा न बने, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच तमाम मन्त्रणाएँ होती होंगी। ज़ाहिर है कि कोई भी शासक वर्ग ऐसी “अन्दरूनी बातों” और “संवेदनशील बातों” को जनता के सामने खोलना नहीं चाहेगा!**

सरकारी वकील के इस तर्क पर न्यायपालिका ने एक प्रकार से सहमति ही जता दी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा मसला भी न्यायपालिका में उठा हुआ है। वह मसला है जजों की सम्पत्ति के विषय में जानकारी को जनता के लिए खुला करना और इसे सूचना के अधिकार के मातहत लाना! इस पर भी न्यायपालिका और सरकार एक प्रकार की सहमति में नज़र आ रहे हैं! कहा जा रहा है कि इससे जजों की निजता ख़तरे

में पड़ जायेगी! आम जनता के तो घरों के भीतर खुफ़ियागिरी करने, उनके ईमेल, फ़ेसबुक आदि पर निगाह रखने, उनके बैंक खातों पर निगाह रखने, उनके फ़ोन टैप करने में भी निजता का अधिकार भंग होता नहीं दिखता है सरकार और न्यायपालिका को, लेकिन जजों की सम्पत्ति को सूचना के अधिकार के तहत लाने से ही उनकी निजता भंग हो जाती है! **सम्पत्ति की जानकारी को सार्वजनिक करने से कैसी निजता भंग होती है?** ज़ाहिर है, मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के तीनों ही अंग यानी सरकार, नौकरशाही-सेना-पुलिस तथा न्यायपालिका आपस में मित्रतापूर्ण सहकार के साथ काम करते हैं। लेकिन ऐसा वे जनता के हितों में नहीं बल्कि जनता के विरुद्ध करते हैं। कारण यह है कि शोषकों और शोषितों में कोई एकता या सहकार नहीं हो सकता है। शोषकों के बीच गहरा सहकार बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या हम मेहनतकश और मज़दूर अपनी वर्ग एकजुटता और संगठन बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं? जब तक हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक अपने तमाम निकायों से मौजूदा शासक वर्ग और उसकी व्यवस्था हमें लूटती रहेगी। इसलिए **भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी** सभी मज़दूरों, कर्मचारियों, ग़रीब किसानों व आम निम्न मध्यवर्ग के लोगों का आह्वान करती है कि आप मज़दूर पार्टी से जुड़ें और शासक वर्ग के संगठन के बरक्स अपना फौलादी और मज़बूत संगठन बनाएं।

# मज़दूर पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाओ!

(पेज 1 से जारी)

की सभाओं में हमारे मुद्दे जैसे कि बेरोज़गारी, महँगाई, ठेका प्रथा का उन्मूलन, सभी श्रम कानूनों को लागू करना, जैसे मुद्दे गायब हैं। नरेन्द्र मोदी खुद “पाकिस्तान-पाकिस्तान”, “हिन्दू-मुसलमान”, वगैरह चिल्ला रहे हैं। हमें बेवकूफ बनाने के लिए “चौकीदार” का जुमला उछाला गया है। लेकिन अगर भाजपा सरकार के नेता-मन्त्री अगर वाकई चौकीदार हैं, तो उन्हें ठेका प्रथा पर 12-12 घण्टे खटने वाले चौकीदारों व सिविलियन गार्डों जितनी तनख्वाह लेनी चाहिए, सारी सुविधाएँ छोड़नी चाहिए, अपनी सुरक्षा पर अरबों रुपये खर्च करने बन्द कर देने चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो इसका अर्थ है कि ‘चौकीदार’ का जुमला आपको मूर्ख बनाने के लिए उछाला गया है।

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में तमाम लोकलुभावन वायदे किये हैं जैसे कि 20 प्रतिशत सबसे ग़रीब परिवारों के व्यक्तियों को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जायेगा, शहरी रोज़गार गारण्टी योजना लायी जायेगी, मनरेगा में 100 की बजाय 150 दिनों का रोज़गार दिया जायेगा, किसानों की कर्ज़ माफ़ी की जायेगी, वगैरह। लेकिन क्या इन वायदों पर भरोसा किया जा सकता है? यह वही पार्टी है जिसने अपने 60 साल के राज में “ग़रीबी हटाओ” जैसे लोकलुभावन नारे देकर देश की सम्पदा को टाटा-बिड़ला जैसे पूँजीपतियों के हाथों बेचा है। यही वह पार्टी है जिसने निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को 1991 में खुले तौर पर शुरू करके मज़दूरों की ज़िन्दगी को तबाहो-बरबाद करने का काम किया था। भाजपा इन्हीं नीतियों को और भी ज़्यादा बेशर्मी और नंगई से आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने जब भी ज़रूरत

पड़ी है तो “सेक्युलरिज़्म” का मुखौटा लगाकर ‘सॉफ्ट केसरिया’ लाइन लागू की है। यही कारण है कि गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों और दलितों का उत्पीड़न मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी जारी है। सच तो यह है कि आम मेहनतकश और मज़दूर इस पार्टी पर कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं।

भाजपा को छोड़कर सभी चुनावी पार्टियों के घोषणापत्र में किसानों के कर्ज़ माफ़ी की बात की गयी है। लेकिन पहली बात तो यह है कि ऐसे वायदे किसानों से पहले भी किये जा चुके हैं और बाद में सभी पार्टियों ने उन्हें धोखा ही दिया है। दूसरी बात यह है कि ऐसी कर्ज़ माफ़ी अगर होती भी है तो इसका फ़ायदा केवल धनी और ऊँचे मँझोले किसानों को ही मिलेगा। कारण यह है कि बड़े बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कर्ज़ उन्हें ही मिलता है और सरकार वही कर्ज़ माफ़ कर सकती है, अगर वह करती है तो। ज़्यादातर ग़रीब किसान और खेतिहर मज़दूर तो गाँव के धनी सूदखोरों, आदतियों और धनी किसानों से ही ऋण लेते हैं, और वह ऋण कभी भी कर्ज़ माफ़ी की योजना के तहत नहीं आयेगा। अगर आँकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या भी इन ग़रीब किसानों ने की है, जिनके पास दो-ढाई हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, या जो छोटी-सी ज़मीन पट्टे पर लेते हैं और फिर कर्ज़ लेकर खेती करते हैं। ज़ाहिर है, कर्ज़ माफ़ी का वायदा कांग्रेस, सपा और अन्य चुनावबाज़ पार्टियाँ केवल बेवकूफ बनाने के लिए कर रही हैं और इन पर कतई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है।

मज़दूरों और ग़रीब किसानों के प्रमुख मसलों पर भाजपा चुप है और कांग्रेस समेत अन्य चुनावबाज़

पार्टियाँ झूठे वायदे कर रही हैं। ऐसे में, आम मेहनतकश आबादी को चुनावों में क्या करना चाहिए? हमें भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, उसका वालण्टियर बनना चाहिए और जहाँ कहीं भी उसके उम्मीदवार खड़े हैं, वहाँ उन्हें उसे एकजुट होकर वोट देना चाहिए। दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से साथी अदिति और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से साथी योगेश, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से साथी रमेश और रोहतक से साथी अरविन्द मज़दूर पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों को मज़दूर वर्ग को एकजुट होकर वोट देना चाहिए और जिताना चाहिए। केवल ऐसे उम्मीदवारों की विजय के ज़रिये मज़दूर वर्ग और ग़रीब किसान आबादी अपने हकों के संघर्ष को आगे ले जा सकती है। केवल ऐसे मज़दूर वर्गीय सांसदों की संसद में मौजूदगी ही आपके क्षेत्र में मज़दूर और मेहनतकश आबादी के लिए तमाम सुविधाओं जैसे पीने के पानी, बिजली, शौचालय व साफ़-सफ़ाई, आदि का इन्तज़ाम कर सकती है और साथ ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानूनों को लागू किया जाय। केवल ऐसे मज़दूर प्रतिनिधियों की संसद में मौजूदगी के ज़रिये हम ठेका प्रथा को समाप्त करने, न्यूनतम मज़दूरी को कम से कम 20 हजार रुपये करने और उसे लागू करवाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन चारों उम्मीदवारों को जिताने के लिए आम मेहनतकश आबादी को एकजुट होकर वोट देना चाहिए और कांग्रेस, भाजपा, इनलो, आम आदमी पार्टी जैसी पूँजीवादी चुनावी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। जहाँ कहीं मज़दूर पार्टी इस बार अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर रही, वहाँ उसे खड़ा करने के प्रयास तुरत शुरू करने चाहिए।

## मोदी क्यों नहीं माँग रहे नोटबन्दी, जीएसटी और ‘अच्छे दिनों’ पर वोट?

नरेन्द्र मोदी अम्बानी-अडानी के पैसों के बूते हेलीकॉप्टरों में घूमघूमकर सभा करनी शुरू कर चुके हैं। इन सभाओं में पैसे दे-देकर भीड़ जुटाई जा रही है, फिर भी आधी कुर्सीयाँ खाली ही रह जा रही हैं। यही कारण है कि मोदी ज़्यादा चीख-चिल्ला रहे हैं! चुनाव भारत का है, मगर वोट पाकिस्तान के नाम पर माँग रहे हैं! हिन्दू-मुसलमान, मन्दिर-मस्जिद, आदि सब पर बात हो रही है, लेकिन ‘अच्छे दिनों’ की बात नहीं हो रही है। यह शब्द मोदी को बुरे सपने की तरह सता रहा है।

यही कारण है कि मोदी अपने सरकार की किसी वास्तविक उपलब्धि की बात नहीं कर रहे। बालाकोट हमले की बातें की जा रही है, हालाँकि उसको लेकर भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अमेरिका ने तो यह भी बता दिया कि

भारत ने पाकिस्तान का कोई एफ़-16 लड़ाकू विमान नहीं गिराया है। लेकिन मोदी सरकार बेशर्मी से झूठ बोले जा रही है। वैसे भी यह भारत का



पहला प्रधानमन्त्री है जो बिना किसी लज्जा के इतना चीख-चीख कर झूठ बोलता है!

लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस नोटबन्दी के बारे में दावा किया गया था कि वह काला धन

समाप्त कर देगा, उसके बारे में मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे। जिस जीएसटी के बारे में कर प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने का दावा किया गया था, उसके बारे में भी मोदी के मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा। न ही 15 लाख रुपये देने, 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष पैदा करने आदि के मोदी के 2014 के वायदों पर मोदी कुछ बोल रहे हैं! क्या इसी से पता नहीं चलता कि मोदी सरकार सभी मामलों में फेल रही है और अब आम मेहनतकश लोगों को धर्म और अन्धराष्ट्रवाद की अफीम सुंघाकर बेवकूफ बना रही है? दोस्तो! इन फ़ासीवादियों के झाँसे में न आएं और चुनावों में इनका पूर्ण बहिष्कार करें। ये मज़दूरों-मेहनतकशों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें इसे हराना ही होगा! यह हमारे अस्तित्व की शर्त बन चुका है।

# जो ठेका प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात न करे, हर उस पार्टी का बहिष्कार करो!

(पेज 1 से जारी)

अपनी फैक्टरियाँ चलवाते हैं! वे भला ठेका प्रथा को क्यों समाप्त करने लगे? नकली कम्युनिस्ट पार्टियाँ इसकी बात ज़रूर करती हैं, लेकिन जहाँ कहीं इनकी सरकार रही वहाँ भी इन्होंने ठेका प्रथा का उन्मूलन नहीं किया। राष्ट्रीय पैमाने पर भी इनके ट्रेड यूनियन फेडरेशन ठेका प्रथा के उन्मूलन के सवाल पर मज़दूरों को धोखा देते रहे हैं। हर आन्दोलन में इन्होंने प्रबन्धन, मालिकान या सरकार के साथ मिलीभगत कर आन्दोलन को बरबाद किया है। ऐसे में, माकपा, भाकपा व भाकपा (माले) लिबरेशन जैसे मज़दूर वर्ग के ग़द्दारों पर तो कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

**आख़िर इन सभी पार्टियों ने ठेका प्रथा के प्रश्न पर हम मज़दूरों और मेहनतकशों को धोखा क्यों दिया है?** कारण यह है कि ठेका प्रथा पूँजीपति वर्ग को हम मज़दूरों से नंगे तौर पर गुलामी करने का मौका देती है। ये सभी पार्टियाँ छोटे, मँझोले या बड़े पूँजीपति वर्ग की नुमाइन्दगी करती हैं। ये सभी पूँजीवादी और निम्न-पूँजीवादी यानी टटपूँजिया चुनावबाज़ पार्टियाँ इन्हीं छोटे, मँझोले और बड़े मालिकों के चन्दे पर चलती हैं। ज़ाहिर है, कि वे इन्हीं मालिकों और ठेकेदारों की ही सेवा करेंगी। माकपा, भाकपा आदि भी हमेशा ही मज़दूरों से ज़्यादा छोटे मालिकों, व्यापारियों आदि के लिए टेसू बहाती रहती हैं। यहाँ उनकी पक्षधरता बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ऐसे में, इन तमाम पूँजीवादी

और टटपूँजिया चुनावबाज़ पार्टियों से यह उम्मीद करना कि वे ठेका प्रथा को समाप्त करेंगी, एक मूर्खतापूर्ण सपना होगा।

मज़दूर भाइयों और बहनो! जिस ठेका प्रथा ने हमारी जिन्दगी को नर्क बना रखा है, उसे पूर्ण रूप से निजी और सरकारी दोनों ही संस्थानों से पूर्ण रूप से ख़त्म करने का वायदा आज कौन कर रहा है? **सिर्फ़ एक पार्टी—भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी।** इस पार्टी पर भरोसा क्यों किया जाय? इसलिए क्यों यह पार्टी पूरी तरह से मज़दूरों और मेहनतकशों के बीच से आने वाले सहयोग और चन्दे पर चलती है। **दूसरी बात** यह कि यह पार्टी स्वयं कारख़ाना मज़दूरों, आँगनवाड़ी कर्मियों, घरेलू कामगारों, कर्मचारियों, बेरोज़गारों नौजवानों और उनके राजनीतिक संगठनकर्ताओं ने बनायी है। इस पार्टी के काडर और लीडर इन्हीं के बीच से आते हैं। **तीसरी बात**, यह पार्टी सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है और इसीलिए यह पार्टी भ्रष्ट और पूँजीवादी पथगामी नहीं हो सकती है। इन तीन कारणों से आप इस पार्टी और इसके कार्यक्रम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।

**यदि आप ठेका प्रथा के खिलाफ़ संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस नयी गुलामी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक वर्ग के तौर पर एकजुट होकर भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी यानी RWPI को वोट दें। उसके**

वालण्टियर बनें। उसे अधिक से अधिक **आर्थिक सहयोग करें।** केवल यही पार्टी ठेका प्रथा को समाप्त करने की ताक़त रखती है। इसलिए जो मज़दूर ठेका प्रथा के विरुद्ध है, उसे इन लोकसभा चुनावों में जहाँ कहीं भी मज़दूर पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, उसे ही वोट देना है। मज़दूर पार्टी के उम्मीदवार दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से खड़े हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र और रोहतक से खड़े हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में दो सीटों और उत्तर प्रदेश में एक सीट पर भी मज़दूर पार्टी के उम्मीदवार हैं। **ये आपके वास्तविक प्रतिनिधि हैं। ये मज़दूर प्रतिनिधि हैं। केवल यही ठेका प्रथा के खिलाफ़ वास्तव में लड़ सकते हैं और यदि कल मज़दूर पार्टी देश में सत्ता में आयी तो वही ठेका प्रथा को समाप्त भी कर सकती है।** इसलिए आज ही अपना वोट मज़दूर पार्टी के उम्मीदवार के लिए पक्का कर लें, यदि आप उत्तर-पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, कुरुक्षेत्र या रोहतक के रहने वाले हैं। जहाँ अभी RWPI के उम्मीदवार नहीं हैं, वहाँ नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध और असन्तोष दर्ज कराएँ और अपने शहर, गाँव या जिले में RWPI के वालण्टियर कोर बनाने के लिए आज ही से कार्य करें।

**मज़दूर पार्टी को वोट दो  
ठेका प्रथा को चोट दो!**

**भाजपा-मोदी के अंधराष्ट्रवाद को बेनकाब करो!**

## सेना को “मोदी सेना” कहना आम सैनिकों का अपमान

लोकसभा चुनाव प्रचार में भाजपा-मोदी चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए सैन्य कार्रवाई और सेना के नाम पर वोटबटोरने में लगे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी से लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चुनावी रैलियों में भारतीय सेना को ‘मोदी की सेना’ बता रहे हैं। ऐसे में सैन्य परिवार व मेहनतकश आबादी को सोचने की ज़रूरत है। अपने आपको “राष्ट्रभक्त” और “देशभक्त” का तमगा खुद ही देकर इतराने वाली नरेन्द्र मोदी सरकार सैनिकों की मौत पर तो घड़ियाली आँसू बहाती है लेकिन जब उन्हीं सैनिकों ने हवाई यात्रा की माँग की थी तो मोदी सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। जब यह हमला हुआ उस समय मोदी उत्तरखण्ड के कॉर्बेट पार्क में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और हमले की सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी थी।

मृत सैनिकों के परिवारजन अभी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि **आख़िर यह हमला सम्भव ही कैसे हुआ? सैनिकों को सीआरपीएफ़ की माँग के बावजूद एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया?**

आरक्षित रास्ते में विस्फोटकों से लदी कार **कैसे पहुँची?** वहीं आज सैनिकों की एयरलिफ्ट की माँग ठुकराने वाली भाजपा आज चुनावी प्रचार के लिए 200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक कर चुकी है जिसका एक दिन का खर्च 10-15 लाख रुपये है। ज़रा सोचिये, मोदी सरकार को सैनिकों की इतनी ही फ़िक्र है तो वह पिछले चार वर्षों से ‘वन रैंक वन पेंशन’ की माँग को स्वीकार करके लागू क्यों नहीं करती? वर्षों से बेहतर खाने और जीवन-स्थितियों की माँग करने वाले सैनिकों को मोदी सरकार बर्खास्त क्यों कर रही है? **जीवित रहते सैनिकों की जायज़ माँगों की कोई सुनवाई नहीं है लेकिन जैसे ही वह एक ताबूत में आता है, वैसे ही उस पर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के प्रयास शुरू हो जाते हैं।**

आज मोदी सरकार पाँच साल की अपनी नाकामी को छिपाने, पूँजीपतियों के तलवे चाटने की अपनी हरकतों के बेनकाब होने और भ्रष्टाचार के दलदल में धँसे होने के कारण अब चुनावों के ठीक पहले युद्धोन्माद भड़का रही है। पिछले कई

चुनावों की ही तरह इस चुनाव के पहले भी एक आतंकी हमला हो गया है! 1999 के लोकसभा चुनावों के पहले कारगिल युद्ध हुआ, 2001 में सात राज्यों के विधानसभा चुनावों के पहले संसद पर आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों के पहले उरी हमला हुआ और अब सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव के पहले पुलवामा हमला हो गया! **जब भी भाजपा सरकार होती है, तो चुनावों से ठीक पहले आतंकवादी हमला क्यों हो जाता है?**

मोदी राज में सैनिकों के हालात बताने वाली गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2014 से 2017 तक बीमारी के चलते 3221 जवान और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। मोर्चे पर बीमारी के चलते मरने वाले जवानों में सबसे बड़ी संख्या सीआरपीएफ़ के जवानों की है। अलग-अलग मोर्चों पर 1489 जवान अभी तक दम तोड़ चुके हैं। वहीं 2018 में सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के 104 जवानों ने आत्महत्या की, 2017 में 101 जवानों ने और 2016 में 129 जवानों ने आत्महत्या की (पेज 6 से जारी)

# भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी ( RWPI ) और क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन के नेतृत्व में मनरेगा मजदूरों ने काम के अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठायी

1 अप्रैल, 2019। कलायत (हरियाणा)। क्रान्तिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन और भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी (RWPI) के बैनर तले गाँव चौशाला के मनरेगा मजदूरों ने कलायत में बीडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रवीन ने बताया कि पिछले कई सालों से मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं दिया जा रहा। गाँव में कम से कम 206 मजदूरों का मनरेगा के तहत जॉब कार्ड भी बना हुआ है जिसको बैंक खाते से भी जोड़ रखा है। यह सब कुछ होने के बाद भी मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ मनरेगा कानून कहता है कि अगर मनरेगा के तहत किसी मजदूर को 15 दिन तक कोई काम नहीं मिलता तो वह बेरोज़गारी भत्ते का हक़दार हो जाता है लेकिन मजदूरों का कहना है कि उनको ऐसे कानून की कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे हालात में वे काम न मिलने की सूरत में कहाँ जाए?

कांग्रेस की सरकार में जिस मनरेगा कानून को लागू किया था उसके तहत ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम 100 दिन का काम दिया जाना चाहिए और कुछ खास परिस्थितियों में यह 150 दिन का भी हो सकता है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि 100-150 दिन काम मिलना तो दूर की बात पिछले लम्बे समय से उनको एक दिन भी काम नहीं मिला है। वैसे तो जब से यह कानून बना है तब से ही वह कागज़ों तक ज़्यादा सीमित है। सत्ता में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की दोनों के समय ही मनरेगा योजना अधिकांश जगहों पर ज़मीनी धरातल पर सही से लागू नहीं हो पाई। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि जितनी बार भी मनरेगा का बजट पास किया गया है उतनी ही बार हज़ारों करोड़

रुपये मनरेगा के तहत खर्च करने की बजाय उसके बड़े हिस्से को बकाया के तौर पर अगले बजट में डाल दिया गया है। जो थोड़ा-बहुत बजट मनरेगा के तहत कागज़ों में लगाया हुआ दिखाया जाता है उसके बड़े हिस्से को भी हर बार ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार के तहत पूरा प्रशासन हजम कर जाता है। अंत में देखा जाए तो इतना सब होने



के बाद मजदूरों को कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय भुखमरी, ग़रीबी, बेरोज़गारी के।

**RWPI कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार साथी रमेश खटकड़** ने कहा कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ-जहाँ मनरेगा का काम चलता है वहाँ सभी जगह ऊपर से नीचे तक प्रशासन के भ्रष्टाचार के केस हर दिन उजागर हो रहे हैं। वैसे तो भाजपा की खट्टर सरकार अपने आप को “भ्रष्टाचार मुक्त” सरकार बताती है लेकिन जो भ्रष्टाचार मनरेगा में कांग्रेस की सरकार के समय से चला आ रहा था वह आज भी भाजपा सरकार में ज्यों का त्यों बना हुआ है, बल्कि पहले से भी बढ़ गया है। सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने मजदूरों से बड़े-बड़े वायदे किए थे जिनमें “अच्छे दिनों” का वायदा भी शामिल था

लेकिन जैसे ही भाजपा की मोदी सरकार सत्ता में आयी वैसे ही अपने सभी वायदों से मुखर गयी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मीडिया के सामने इन सभी वायदों को जुमला करार दे देते हैं। NSSO का आँकड़ा बताता है कि पिछले एक साल के दौरान एक करोड़ दस लाख लोगों के रोज़गार छिन चुके हैं। जिस मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने का वायदा किया था उसने नौकरियाँ देना तो दूर पाँच साल में पौने चार करोड़ लोगों का रोज़गार छिन लिया है। इस दौरान जिन लोगों का रोज़गार छिना है उनमें सबसे ज़्यादा मजदूर आबादी शामिल है। आँकड़े बताते हैं की पिछले पाँच सालों में मोदी सरकार ने देश की मेहनतकश जनता को रोज़गार देने की बजाय जाति-धर्म के नाम पर सिर्फ़ दंगे-फ़साद और मार-काट कराई है। आज जिन हालात से देश गुज़र रहा है उसमें जाति-धर्म की लड़ाई को छोड़ कर मेहनतकश जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है। किसी भी पूँजीवादी चुनावबाज़ पार्टी के भरोसे न रह

कर, मेहनतकश लोगों को चुनाव में भी अपना विकल्प खड़ा करने की ज़रूरत है। भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी जिसे स्वयं मजदूरों-मेहनतकशों और उनके राजनीतिक संगठनकर्ताओं ने बनाया है और जो उन्हीं के संसाधनों पर चलती है, ऐसी ही एक पार्टी है और मनरेगा मजदूरों ने अपने प्रदर्शन के दौरान उसे समर्थन और वोट देने की घोषणा की। अंत में मजदूरों का कहना था की अगर उनको जल्द से जल्द मनरेगा के तहत काम नहीं मिला तो वह अपने आन्दोलन को अपने गाँव के साथ-साथ आस-पास के दूसरे गाँव में भी फैला कर ओर तेज़ करेंगे। **RWPI ने इस आन्दोलन को पूर्ण समर्थन दिया और कुरुक्षेत्र से जीतने की सूरत में मनरेगा मजदूरों की माँगों को पूरा करवाने का वायदा किया।**

## दिल्ली स्टेट ऑगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन ने दिया मजदूर पार्टी ( RWPI ) को समर्थन

5 अप्रैल को आयोजित यूनियन की आम सभा में दिल्ली स्टेट ऑगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन ने जारी लोकसभा चुनावों में भारत की क्रान्तिकारी मजदूर पार्टी (RWPI) को बाकायदा समर्थन देने की घोषणा की। यूनियन की सचिव शिवानी कौल ने कहा कि चूँकि RWPI हमारी यूनियन की सभी बुनियादी माँगों को अपने घोषणापत्र में स्वीकार करती है और उसके लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यूनियन ने सर्वसम्मति से RWPI को समर्थन देने की घोषणा की है।

लिए संघर्षरत है, बल्कि वह एक ऐसा घोषणापत्र और एजेण्डा लेकर चुनावों में आयी है, जिसे सच्चे



यूनियन की कार्यकारिणी की सदस्य मनीषा ने कहा कि न सिर्फ़ मजदूर पार्टी हमारी समस्त यूनियन माँगों को स्वीकार करती है और उसके

मायने में मजदूरों, स्त्रियों और युवाओं का एजेण्डा कहा जा सकता है। यूनियन कार्यकारिणी की सदस्य पूनम ने कहा कि इस पार्टी पर भरोसा करने का

कारण यह है कि इस पार्टी को स्वयं मजदूरों, ऑगनवाड़ीकर्मियों, बेरोज़गार युवाओं और कर्मचारियों ने बनाया है। दूसरी वजह यह है कि यह पार्टी अम्बानी, अडानी, टाटा, बिड़ला जैसे पूँजीपतियों, ठेकेदारों और दलालों से चन्दा नहीं लेती बल्कि स्वयं मजदूर वर्ग और आम मेहनतकश आबादी के बीच से अपने संसाधनों को जुटाती है।

यूनियन प्रवक्ता वृशाली ने कहा कि टॅच के समर्थन में पहले ही यूनियन ने उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के संसद क्षेत्र में सभाओं की शुरुआत कर दी है। इन बैठकों और सभाओं में ऑगनवाड़ीकर्मी RWPI को उसके जनपक्षधर एजेण्डा के कारण पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और वे चुनावों में मजदूर पार्टी का प्रचार भी करेंगे।

# क्या मोदी मज़बूत नेता है?

पूरे देश में चुनावों के पहले भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। न तो रोज़गार के बारे में वह कुछ बोल रही है, न काले धन के बारे में, न किसानों की कर्ज़ माफ़ी के बारे में और न ही “अच्छे दिन” के बारे में! वह एक ही राग अलाप रही है: मोदी नहीं तो कौन? मोदी ही ताक़तवर नेता है! मोदी ही मज़बूत नेता है! सर्जिकल स्ट्राइक और अन्धराष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, हालाँकि अन्तरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मित्र अमेरिका स्वयं बोल रहा है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में न तो आतंकवादी मारे गये हैं और न ही पाकिस्तान का कोई एफ़-16 जहाज़ गिराया गया है। लेकिन मोदी-शाह के टुकड़ों पर पलने वाला कारपोरेट मीडिया चीख-चीखकर मोदी को “ताक़तवर” नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा है? आइये देखते हैं।

मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवादी हमलों में 94 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। भारत के इतने सैनिक किसी अन्य शासन में नहीं मरे जितने कि अकेले मोदी राज में मरे हैं। **क्या यह “मज़बूत” नेता की निशानी है?**

पुलवामा हमले में मारे गये सैनिकों ने हवाई मार्ग से ले जाये जाने की माँग की थी। लेकिन अपने चुनाव प्रचार में रोज़ 40 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाले मोदी और उसकी सरकार ने सैनिकों की प्रार्थना ठुकरा दी, जिसके कारण 44 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? **क्या यह “ताक़तवर” नेता की निशानी है?**

दमित राष्ट्रीयताओं के अलगाव को मोदी सरकार ने किसी भी अन्य सरकार से ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिसके कारण कश्मीर से लेकर उत्तर-पूर्व तक दमित राष्ट्रीयताएँ अपने आपको अलग-थलग महसूस कर रही हैं। हमेशा ही सैन्य दमन के कारण वे अलगाव का शिकार थीं, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यह अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। **क्या यह “फ़ैसला लेने वाले नेता” की पहचान है?**

असम में नागरिकता संशोधन बिल लाकर जनता को आपस में लड़ा देने की साज़िश भी मोदी सरकार ने ही की है। क्या यह देश की जनता की एकजुटता को कायम रखना है? **क्या यह “शक्तिशाली” नेता की निशानी है?**

देश में पिछले पाँच वर्षों में मोदी सरकार ने पौने चार करोड़ लोगों के रोज़गार छीन लिये। जीएसटी और नोटबन्दी ने पहले से मन्दी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और ऊपर से मोदी सरकार फ़र्जी आँकड़े और झूठ बोलकर 7 प्रतिशत की वृद्धि दर का खोखला दावा कर रही है। **क्या यह “मज़बूत नेता” की निशानी है?**

देश में खेती का संकट अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। ग़रीब किसानों की भारी संख्या ज़मीनों को बेचकर मज़दूरों की कतार में शामिल हो गयी। कर्ज़ माफ़ी की 2014 की मोदी की घोषणा एक जुमला साबित हुई। **क्या ये सब तथ्य किसी “निर्णायक नेता” की ओर इशारा करते हैं?**

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को मोदी सरकार ने तबाह कर दिया है। बैंकों की हालत दयनीय हो

रखने के लिए रिज़र्व बैंक के आरक्षित धन को भी ख़र्च कर रही है। देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट की कगार पर आ खड़ा हुआ है। **क्या यह किसी “मज़बूत नेता” की निशानी है?**

देश से दर्ज़नों घोटालेबाज़ उद्योगपति व व्यवसायी जैसे कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भाग चुके हैं और मोदी सरकार उन्हें न सिर्फ़ वापस न ला सकी, बल्कि ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन भगोड़ों को स्वयं मोदी सरकार ने ही भगाने में मदद की है। **क्या यह किसी “ईमानदार” नेता की निशानी है?**

राफ़ेल घोटाले में मोदी सरकार पूरी तरह नंगी हो गयी और यह सामने आ गया कि मोदी सरकार रिलायंस जैसे उद्योगपतियों के सामने कैसे नतमस्तक है। देश के छह एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिये गये, लाल किला तक उसे बेच दिया गया! **क्या यह किसी “मज़बूत नेता” की निशानी है?**

ज़रा सोचिये दोस्तो! मोदी सरकार के झूठे प्रचार में मत फँसिये। यह “मज़बूत सरकार” नहीं बल्कि पूँजीपतियों के सामने नतमस्तक और बिकी हुई सरकार है। इसे सत्ता से हटाए बिना मज़दूर वर्ग की बरबादी होगी। फासीवादी भाजपा को हराना, मज़दूर वर्ग का सबसे अहम तात्कालिक लक्ष्य है। यह भी तभी सम्भव है जबकि मज़दूरों-मेहनतकशों की स्वतन्त्र आवाज़ संसद तक पहुँचे। RWPI इसी मक़सद के साथ चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है और हमें इसे जिताना होगा।

## सेना को “मोदी सेना” कहना आम सैनिकों का अपमान!

( पेज 1 से जारी )

थी। इनमें से ज़्यादातर मज़दूरों, किसानों या कुछ मध्यवर्गीय घरों के युवा ही हैं। स्पष्ट है कि सैनिकों की इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार ताक़तें जब देशभक्ति और “राष्ट्रभक्ति” की बात करती हैं, तो उनके देश और “राष्ट्र” में आम मज़दूर, ग़रीब किसान और मेहनतकश नहीं होते! **सच यह है कि उनके “राष्ट्र” में हम मेहनतकश कहीं नहीं हैं।** हमारा काम सिर्फ़ यह है कि हम अम्बानियों-अडानियों के लिए मरते-खपते रहें, चाहे कारखानों, खलिहानों में या फिर सरहद पर।

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी का

घोषणापत्र स्पष्ट करता है कि आज सैनिकों का सच्चे मायने में समर्थन करने का अर्थ है कि हम उनकी जायज़ माँगों का समर्थन करें, सेना में उनकी जीवन व कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने की उनकी माँगों का समर्थन करें और ‘वन रैंक वन पेंशन’ की माँग का समर्थन करें। त्त्व का सैनिकों व पुलिस बलों हेतु निम्न एजेण्डा है

1. पुलिस और सेना को शान्ति काल में उत्पादक कार्रवाइयों में लगाया जाना चाहिए और उन्हें सभी जनवादी अधिकार जैसे कि राजनीतिक साहित्य का अध्ययन करना, यूनियन बनाना, हड़ताल करना, आदि दिये जाने चाहिए। सेना और पुलिस में अर्दलियों

की व्यवस्था तत्काल समाप्त की जानी चाहिए। सेना के भीतर अधिकारियों का सैनिकों द्वारा चुनाव होना चाहिए। एक चुने हुए सैन्य अधिकारी की ही सच्ची मान्यता और प्राधिकार हो सकता है।

2. हथियारों की ख़रीद और सेना के अधिकारियों के विशेषाधिकारों पर होने वाले भारी-भरकम ख़र्च में कटौती की जाये।

3. वन रैंक वन पेंशन की सैनिकों की माँग को तत्काल स्वीकार किया जाये।

4. सैन्य बलों, अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस बल में रैंक के अनुसार खान-पान व रहन-सहन में विभेद की व्यवस्था को समाप्त किया जाये।

## क्या आपको पता है?

मौजूदा संसद में करीब 33 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं, जिन पर हत्या, बलात्कार, दंगा करवाने, घपले करने आदि जैसे मुकदमे दर्ज़ हैं! इनमें से सबसे ज़्यादा आरोपी सांसद अपने चाल-चेहरा-चरित्र और भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली धर्मध्वजाधारी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अन्य पार्टियों की स्थिति भी ऐसी ही है। ये सभी करोड़पति और अरबपति तक हैं। क्या आप इतने भोले और नादान हैं कि आपको लगता है कि ऐसे लोग आपकी नुमाइन्दगी करेंगे? ज़रा सोचिये! केवल और केवल जनता के बल और धन पर खड़ी पार्टी ही आपका प्रतिनिधित्व कर सकती है, और वह पार्टी है – **भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI)। मज़दूर पार्टी को वोट दें! मज़दूर उम्मीदवार को जिताएँ! अपने हकों के संघर्ष को आगे बढ़ाएँ!**

## नहीं चुनेंगे बुरा विकल्प, खड़ा करेंगे अपना पक्ष! यूनियन आमसभा में दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन ने लिया फैसला भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी ( RWPI ) ही हमारा पक्ष है!

गत 6 अप्रैल को दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन ने शाहबाद डेरी इलाके में अपनी आमसभा का आयोजन किया। आमसभा में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मेहनतकशों के स्वतंत्र पक्ष को यूनियन द्वारा समर्थन दिया जाएगा, जिसकी नुमाइंदगी भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) कर रही है। घरेलू कामगार यूनियन की बीना ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी मेहनतकश अवाम की ज़िन्दगी में कोई बदलाव नहीं आया है बल्कि हालात और भी बदतर हुए हैं। अमीरी और ग़रीबी की खाई दिनों-रात चौड़ी होती गयी है। एक तरफ बड़ी-बड़ी कोठियाँ खड़ी हुई हैं तो दूसरी तरफ इन कोठियों को खड़ा करने वाली बड़ी आबादी को गन्दी झुगियाँ और कूड़े के ढेर पर ही जीना पड़ रहा है। अपनी सभी बुनियादी ज़रूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास आदि से हम आज भी वंचित हैं। हर पाँच साल में हमने किसी न किसी पार्टी को चुना लेकिन इन्होंने हमारी

बुनियादी ज़रूरतों के लिए कुछ काम नहीं किया। घरेलू कामगारों की ही बात करें तो हम लोग 10 घण्टे तक बड़ी-बड़ी कोठियों में काम करते हैं, कोठियों में रहने वाले लोगों की ज़िन्दगियाँ आसान बनाते हैं। लेकिन बदले में हमें इतना भी नहीं मिलता कि वह एक इंसानी ज़िन्दगी के लिए काफी हो। ऊपर से रोज़-रोज़ ज़िल्लत और अपमान सहना हमारी ज़िन्दगी का हिस्सा है। हर रोज़ हमें मालकिनों की मुँहदेखी और ठकुरसुहाती करनी पड़ती है।

ऐसा इसलिए है कि हमें मज़दूर नहीं समझा जाता। दिल्ली में इस समय लगभग 5 लाख घरेलू कामगार हैं। हमारे लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। हम गुमनामी में काम करते हैं। इसी बात का फ़ायदा मालिकों को मिलता है। हमारे लिए किसी भी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है। हाँ, बातें सबने की हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ बातें नहीं ठोस-ठोस काम चाहिए। अभी तक किसी चुनावबाज पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में हमारे बारे में एक लफ़्ज़ नहीं कहा था। RWPI एकमात्र ऐसी

पार्टी है जिसने हमारी तक़लीफ़ों को समझा है और हमारी माँगों अपने चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया है। काम की जगहों के अलावा हम जहाँ रहते हैं उस इलाके में भी बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। शाहबाद डेरी में पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है जो गर्मी के दिनों में विकट बन जाती है। इसके अलावा डिस्पेंसरी, नालियों की साफ़-सफ़ाई, झुगियों की जगह पक्के मकान भी बड़े मुद्दे हैं जिनसे किसी भी नेता-मंत्री का कोई मतलब नहीं है। RWPI इन मसलों पर भी एक स्पष्ट सोच और कार्यक्रम रखती है। इसलिए हमें लगता है कि अब अमीरों की नुमाइंदगी करने वाली चुनावबाज पार्टियों से उम्मीद लगाना खुद को धोखा देना है। 70 सालों से हम नागनाथ, साँपनाथ, गिरगिटमल में से किसी एक को चुनते आए हैं। लेकिन अब और नहीं! अब हम अपना उम्मीदवार, अपना पक्ष खुद खड़ा करेंगे। मेहनतकशों की क्रान्तिकारी पार्टी, भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी ही हमारा विकल्प है।

## बवाना के मज़दूरों के जीवन की परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं सभी पूँजीवादी चुनावी पार्टियाँ! मज़दूर पार्टी ही एकमात्र विकल्प है!

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डीएसआईआईडीसी के मातहत लघु उद्योगों को बसाया गया। इसके अलावा यहाँ बड़ी कम्पनियाँ प्रगति पॉवर प्लान्ट, डीएमएसडब्लू और सैल जैसी कम्पनियाँ भी हैं। बवाना में 16350 प्लॉट में 12000 फैक्टरियाँ हैं और इनमें हजारों मज़दूर काम करते हैं। अधिकतम फैक्टरियों में मज़दूर 5000-6000 रुपये में काम करते हैं। ये कम्पनियाँ मज़दूरों को जमकर लूटती हैं। यह बात हम मज़दूरों को समझनी होगी कि मज़दूरों की सबसे बर्बर लूट अक्सर छोटे फैक्टरी मालिकों द्वारा होती है। बवाना में कई छोटे मालिक फैक्टरी किराए पर लेकर चला रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गैरकानूनी है। किराए पर चल रही फैक्टरियों के बारे में अधिकतर सरकारी विभागों को कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि ये फैक्टरियाँ किसी श्रम कानून का पालन नहीं करती हैं क्योंकि सरकार की नज़र में ये अस्तित्व में ही नहीं है। यही कारण है कि ये फैक्टरियाँ किसी भी प्रकार के अग्निशमन व सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करती हैं। पिछले साल बवाना की फैक्टरियों में आग लगने पर जब बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का घेराव किया गया तो डीएसआईआईडीसी ने इन फैक्टरी मालिकों को नोटिस दिया कि इन फैक्टरियों में कानूनों का पालन किया जाए। अब चूँकि ये छोटे फैक्टरी

मालिक ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक चन्दा देते हैं इसलिए



बवाना औद्योगिक क्षेत्र में RWPI की एक जनसभा

कम्पनी का मालिकाना फ्रीहोल्ड पर लेने के लिए, जिससे वे डीएसआईआईडीसी की कार्यवाही से बच सकें, इन्होंने आम आदमी पार्टी के मन्त्री से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने इन मालिकों को इस कार्यवाही से बचाने के लिए विधनसभा से कानून बनाने की बात कही है। ये छोटे मालिक 2018 में ही भाजपा के सांसद उदित राज से भी मिले जिन्होंने कहा कि बवाना के मालिकों ने 1994 से बहुत मेहनत कर ये फैक्टरियाँ खड़ी की हैं! उदित राज ने भी बवाना के फैक्टरी मालिकों को ज़मीन फ्रीहोल्ड पर दिलवाने की

माँग की। परन्तु भाजपा और आम आदमी पार्टी इन फैक्टरियों में मज़दूरों के हक़-अधिकारों पर कुछ भी न बोले। क्योंकि मज़दूरों की लूट से बवाना के मालिक जो मुनाफ़ा पीटते हैं उससे ही ये भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चन्दा देते हैं। इसलिए ये मज़दूरों की मौत पर चुप ही रहेंगे। ये ठेकेदारों द्वारा पैसा मारे जाने पर चुप ही रहेंगे। ये हमारी लाशों पर मुनाफ़ा पीटने वाले, हमारी हड्डियों के चूरे को बाज़ार में बेचने वाले छोटे फैक्टरी मालिकों के ही प्रतिनिधि हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में हम अगर इन पूँजीवादी पार्टियों को वोट देंगे तो अपनी मौत के सौदागरों को वोट देंगे। इस बार हम केवल और केवल मज़दूरों की अपनी पार्टी भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) की उम्मीदवार अदिति को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट से विजयी बनाएँ। भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी पिछले 15 सालों से मज़दूरों को संगठित करने वाले मज़दूर कार्यकर्ताओं और मज़दूरों ने बनायी है जो बवाना में पिछले साल आग लगने से हुई मौतों के खिलाफ़ मज़दूरों को संगठित कर रहे हैं। बवाना में मज़दूरों की क्रान्तिकारी यूनियन बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन भी भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) की उम्मीदवार अदिति को अपना समर्थन दे रही है।

## पूँजीपतियों की पार्टियों को जानो-2 कांग्रेस किसकी पार्टी है?

- कांग्रेस पार्टी देश के बड़े पूँजीपतियों की सबसे पुरानी पार्टी है।
  - कांग्रेस को 2017-18 में इन पूँजीपतियों से लगभग 200 करोड़ रुपये का चन्दा मिला है।
  - कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने ठेकेदारी, निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की शुरुआत 1991 में नयी आर्थिक नीतियों के साथ की थी।
  - कांग्रेस ने ही “समाजवाद” का जुमला उछालकर पहले बैंकों का राष्ट्रीकरण किया ताकि उससे अरबों रुपये का कर्ज टाटा, बिड़ला आदि को दिया जा सके। बाद में, कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने इस कर्ज को माफ़ भी कर दिया। यानी जनता का पैसा पूँजीपतियों की जेबों में डाल दिया गया।
  - आज़ादी के बाद हुए जीप घोटाले से लेकर 2-जी घोटाले तक इस पार्टी ने घोटाले करने का एक काला इतिहास लिखा था, हालाँकि भाजपा ने इसे अपने पाँच साल के राज्य में ही घपले-घोटाले में पीछे छोड़ दिया है।
  - कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी के बाद जो संविधान सभा बुलायी थी, वह देश की जनता ने नहीं बल्कि पूँजीपतियों और ज़मीन्दारों ने चुनी थी। इस प्रकार देश की राजनीतिक बुनियाद यानी संविधान बनाने में देश की जनता को कोई भूमिका नहीं दी गयी।
  - देश में मज़दूरों का दमन करने में भी कांग्रेस पीछे नहीं रही है। बेलछी-बेलाडीला काण्ड, पंतनगर काण्ड से लेकर मारुति सुजुकी के मज़दूरों के दमन तक में, कांग्रेस ने पूरी वफ़ादारी से पूँजीपतियों की हित रक्षा में मज़दूरों-मेहनतकशों पर डण्डे-गोलियाँ चलाए हैं।
  - कांग्रेस के मौजूदा चुनाव घोषणापत्र में तमाम लोकलुभावन वायदों के साथ यह भी कहा गया है कि पूँजीपतियों को उद्योग लगाने व चलाने की पूरी छूट दी जायेगी और उन्हें धंधा करने की हर सुविधा दी जायेगी। यानी, श्रम कानूनों सम्बन्धी सभी बाधाओं से मुक्ति का कांग्रेस ने पूँजीपति वर्ग से वायदा किया है। यही असली वायदा है! बाकी धोखा है!
- भाजपा से तंग आकर पूँजीपतियों की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को वोट देना हम मज़दूरों-मेहनतकशों के लिए कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास आज अपनी राजनीतिक पार्टी RWPI मौजूद है। कल तक विकल्प नहीं था! हमारे पास इस या उस पूँजीवादी पार्टी को वोट देना मजबूरी था! मगर आज ऐसा नहीं है! इसलिए RWPI के उम्मीदवार को वोट दें! अपने स्वतन्त्र राजनीतिक स्वर को शक्तिशाली बनाएँ!**

## मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में मज़दूरों के नारकीय हालात और मज़दूर पार्टी का संकल्प

मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ हर तरह की फैक्टरियाँ चलती हैं, जैसे कि जूता, प्लास्टिक, गत्ता, कैमिकल आदि। यहाँ हर फैक्टरी में 12-12 घण्टे की 2 शिफ्ट में काम होता है। सभी फैक्टरियों में औसतन 30-40 मज़दूर काम करते हैं। यहाँ अधि कतम आय 7000-8000 रुपये तक है। अधिकांश फैक्ट्री लिमिटेड कम्पनियाँ नहीं हैं परन्तु हर फैक्ट्री पर लिमिटेड कम्पनी का झूठा बैनर लगा है। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र में घूमें तो पाएँगे कि स्टील की फैक्टरी में काम करने वाले मज़दूर खुले में काम करते हैं। उनके ऊपर छाँव तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। कड़कती धूप और नीचे तपती लोहे की मशीन पर ये मज़दूर काम करते हैं। छुट्टी करने पर मालिक पैसे काट लेता है। RWPI के वालण्टियर को इलाके में काम में लगे एक दिहाड़ी मज़दूर ने बताया कि उनको कभी 350 तो कभी 250 रुपये

तक दिहाड़ी मिलती है। लेकिन ये पक्का नहीं है कि काम मिलेगा या नहीं। बहुत मुश्किल से घर का काम चलता है। RWPI के वालण्टियरों ने चुनाव प्रचार करते हुए मज़दूरों से बात करने के लिए कई फैक्टरियों में अन्दर जाने की कोशिश की लेकिन वे कुछ ही में अन्दर जा पाए।

एक फैक्ट्री के बाहर जॉब का इशतहार देखकर RWPI के वालण्टियर काम लेने के बहाने अन्दर गए। अन्दर लोहे का काम हो रहा था जिनमें लोहे के रैक बन रहे थे। वहाँ काम करने के लिए पर्याप्त रोशनी तक की सुविधा नहीं थी। उसके बाद मालिक से मुलाकात पर पता चला कि 8 घण्टे के महिलाओं को 5500 रुपये दिए जाते हैं। एक अन्य फैक्टरी में पैकिंग का काम कराया जाता था। काम देखने के बहाने पता चला कि फैक्टरी में हर जगह धूल व कैमिकल की गंध फैली हुई थी जिससे सांस लेने में

भी मुश्किल हो रही थी। वहाँ पर नीचे बनने वाले लोहे की रैक वगैरह पर पेंट करने का काम और टेप चिपकाने जैसा काम हो रहा था। यहाँ काम कर रहे मज़दूरों ने बताया कि यहाँ 12 घण्टे के काम का महिलाओं को 5500 तथा पुरुषों को 7500 रुपये तक वेतन मिलता है। हर जगह कैमरे लगा कर मज़दूरों पर निगरानी रखी जाती है। उनको फोन तक करने की इजाज़त नहीं होती। ये हालात आज सिर्फ मुंडका ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे मज़दूरों के हैं।

**RWPI का यह संकल्प है कि वह यदि दिल्ली में किसी भी सीट पर विजयी होती है, तो दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में जारी मालिकों और ठेकेदारों की इस मनमानी को बन्द करवाया जायेगा और सभी श्रम कानूनों को लागू करवाया जायेगा और नियमित जाँच की व्यवस्था की जायेगी।**

## भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) की सभी मेहनतकशों व मज़दूरों से अपील

- मज़दूर पार्टी (RWPI) को वोट दें!
- मज़दूर पार्टी के वालण्टियर बनें!
- अपने इलाके में मज़दूर पार्टी की बैठक कराएं!
- मज़दूर पार्टी को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें!

सम्पर्क: 9873358124, 9289498250, 8685030984, 9812764062, पता: बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-94

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी हेतु सनी सिंह द्वारा प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, शाहदरा द्वारा मुद्रित। सम्पादक: सनी सिंह। बुलेटिन सं. 2, 5 अप्रैल 2019,

सम्पादकीय कार्यालय : बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, दिल्ली-94